प्रदेशाध्यक्ष के फैसले के लिए शाह ने बड़े नेताओं को कल दिल्ली बुलाया

मुख्यमंत्री राजे, ओम माथुर, भूपेंद्र यादव समेत प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य रहेंगे मौजूद

पॉलिटिकल रिपोर्टर. जयपुर।

दो माह से बिना अध्यक्ष डांवाडोल स्थिति से गुजर रही भाजपा की प्रदेश इकाई को जल्द ही नया चेहरा मिल सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अध्यक्ष के नाम पर फैसला करने के लिए प्रदेश के बड़े नेताओं को 13 जून को दिल्ली बुलाया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा इस बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भूपेंद्र यादव, ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, सीआर चौधरी, राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़, परिवहन मंत्री यूनुस खान और सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी के मौजूद रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इन नेताओं के अलावा भी कुछ प्रमुख लोगों को शाह ने दिल्ली बुलाया है। इनमें केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद मदनलाल सैनी और रामनारायण डूडी सहित कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जो अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, सह संगठन महामंत्री वी.सतीश और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना की भी मौजूदगी रहेगी।

16 अप्रैल को अशोक परनामी का इस्तीफा होने के बाद लगभग दो माह से पार्टी में अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। अध्यक्ष पद पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तय हुआ लेकिन केंद्र की ही पसंद पर प्रदेश नेतृत्व की सहमति नहीं मिलने के कारण घोषणा अटक गई थी। तब से लेकर अब तक पार्टी के कई नेताओं के नाम इस पद के लिए चर्चा में आ चुके हैं लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी।

अब माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों की नजदीक आ रही तारीखों को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर गंभीर हो गया है। दिल्ली बुलाए गए नेताओं से शाह वन-टू-वन भी कर सकते हैं और सामूहिक तौर पर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि इस बैठक के बारे में पार्टी नेता खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।

स्वीपर-कुक भर्ती के लिए 20 दिन बाद भी नहीं मिला मार्गदर्शन

जयपुर | आरएसी पांचवी बटालियन में कुक व स्वीपर के नौ पदों के लिए आए 1177 आवेदनों में से 977 को सामान्य जांच के दौरान भर्ती कमेटी द्वारा निरस्त करने के मामले में बटालियन ने पुलिस मुख्यालय को फाइल भेजकर मार्ग दर्शन मांगा कि भर्ती कराए या नहीं। मगर पुलिस मुख्यालय 20 दिन बाद भी यह तय नहीं कर पाया कि बटालियन को क्या राय भेजे। जिसके चलते भर्ती अटक गई है। फाइल पुलिस मुख्यालय में हैडक्वाटर विंग के पास है। आरएसी पांचवी बटालियन में कुक के दो पदों व स्वीपर के पांच पदों के लिए दिसंबर 2017 तक आवेदन मांगे थे। जिसमें 1177 आवेदकों ने आवेदन किया था।

दसवीं बोर्ड का परिणाम जारी : झुंझुनूं का परिणाम 86.99%

शेखावाटी छाया, देवनानी का गृह जिला 16वें स्थान पर

अजमेर | राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम में शेखावाटी बेल्ट छाया नजर आ रहा है। परिणाम देने में झुंझुनूं जिला 86.99 प्रतिशत परिणाम के साथ सिरमौर बना, जबकि इसी बेल्ट के सीकर जिले का दूसरा नंबर रहा। सीकर का कुल परिणाम 86.88 फीसदी रहा। तीसरे नंबर पर 84.70 प्रतिशत के साथ नागौर जिला रहा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का गृह जिला अजमेर 16वें स्थान पर रहा है। अजमेर से आगे भीलवाड़ा और टोंक नजर आ रहे हैं।

10वीं, 12वीं फेल साल बचायें
अक्टूबर 2018 में पास करें
NIOS का Authorised Center(AI-170217)
R.K. School
A-183, Girnar Colony, Vaishali Nagar, Jaipur
9829115898, 9001995898

चौथे नंबर पर जालौर जिला रहा। यहां के विद्यार्थियों का परिणाम 83.10 प्रतिशत रहा। पांचवे नंबर पर जोधपुर जिला है। यहां का परिणाम 83.08 प्रतिशत रहा। छठे नंबर पर 83.06 प्रतिशत के साथ बाड़मेर जिला रहा। सातवें नंबर पर 82.99 प्रतिशत के साथ चूरू जिला रहा। आठवें नंबर पर 82.61 के साथ जयपुर जिला रहा। नौवें नंबर पर हनुमानगढ़ 81.73 प्रतिशत रहा। 10वें स्थान पर बीकानेर 81.37 के साथ रहा। 11 वें स्थान पर 80.90 प्रतिशत के साथ दो जिले अलवर और भीलवाड़ा रहे हैं। 12वें नंबर पर 80.46 प्रतिशत के साथ श्रीगंगानगर, 13वें स्थान पर 79.86 प्रतिशत के साथ टोंक, 14 वें स्थान पर 79.81 प्रतिशत के साथ चित्तौड़गढ़ जिला रहा।

बोर्ड ने प्रवेशिका का परिणाम घोषित किया

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रवेशिका परीक्षा 2018 का परिणाम सोमवार अपराह्न घोषित कर दिया। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से कुल 7041 विद्यार्थियों ने आवेदन किए। इनमें से 6863 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। कुल 62.51 प्रतिशत परिणाम रहा।

प्रवेशिका में 62.51% रहा रिजल्ट

अजमेर | माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से सोमवार को जारी प्रवेशिका परीक्षा 2018 का परिणाम 62.51 फीसदी रहा। प्रवेशिका के परिणाम में छात्राओं ने बाजी मार ली। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 63.32 तथा छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 61.56 रहा। परीक्षा के लिए 7041 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए थे, जिनमें छात्रों की संख्या 3258 तथा छात्राओं की संख्या 3783 रही। परीक्षा में कुल 6863 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें 3150 छात्र तथा 3713 छात्राएं थीं। छात्रों में प्रथम श्रेणी से 432, द्वितीय श्रेणी से 963 तथा तृतीय श्रेणी से 537 उत्तीर्ण हुए, जबकि 7 को सिर्फ उत्तीर्ण घोषित किया गया। पूरक परीक्षा के योग्य 254 परीक्षार्थी माने गए। कुल 1939 छात्रों के साथ उत्तीर्ण प्रतिशत 61.56 फीसदी रहा।

- **507 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण:** इसी प्रकार छात्राओं में प्रथम श्रेणी से 507, द्वितीय श्रेणी से 1279 तथा तृतीय श्रेणी से 535 उत्तीर्ण हुईं, जबकि 30 को सिर्फ उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसके अलावा 294 छात्राओं को पूरक योग्य माना गया। कुल 2351 छात्राओं के साथ उत्तीर्ण प्रतिशत 63.32 फीसदी रहा।
- **कुल 939 की प्रथम श्रेणी :** छात्र और छात्राओं को मिलाकर प्रथम श्रेणी से 939, द्वितीय श्रेणी से 2242, तृतीय श्रेणी से 1072 तथा केवल उत्तीर्ण 37 रहे। कुल 4290 विद्यार्थियों के साथ उत्तीर्ण प्रतिशत 62.51 फीसदी रहा।

आईटी सब्जेक्ट में बढ़ा रुझान

दसवीं बोर्ड के सोमवार को जारी परिणाम में यह भी सामने आया कि विद्यार्थियों का रुझान अब आईटी के क्षेत्र में बढ़ रहा है। दसवीं में वोकेशनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा 8745 स्टूडेंट्स आईटी एंड आईटीज सब्जेक्ट के रहे। दसवीं के परिणाम के आधार पर और 11वीं में विषय चयन के साथ ही यह तय कर लिया जाता है कि बच्चे को किस फील्ड में जाना है या कौनसा प्रोफेशन चुनना है। पिछले कुछ सालों में आईटी की ओर विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है, इसका सीधा असर दसवीं में भी अब देखने को मिल रहा है। यहां वोकेशनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आईटी में होना यही बता रहा है। अन्य वोकेशनल विषयों की ओर देखें तो सबसे कम ऑटोमोबाइल में 726 स्टूडेंट्स रहे।इसके अलावा ब्यूटी एंड वेल में 5539, हैल्थ केयर में 7070, रिटेल में 1556, ट्रैवल एंड टूरिज्म में 1258, सिक्यूरिटी में 1969, एप. मेड होम में 1134, इले. एंड इलेक्ट्रोन में 2340 तथा माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में 1074 स्टूडेंट्स शामिल हुए।

10वीं / 12वीं फेल साल बचायें
5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं सीधे 10वीं पास करे
NIOS भारत सरकार का अधिकृत केन्द्र
जी. कैरियर सी. सै. स्कूल
नगर पालिका के पास, कि. रेनवाल (जयपुर)
मो. 9929584017, 9680472014, 9829522549

7 सब्जेक्ट में अधिकतम अंक 100

दसवीं बोर्ड के परिणाम में विद्यार्थियों के 7 विषयों में अधिकतम 100 आए। इसमें हिंदी विषय भी शामिल है, जिसमें पूरे अंक आना अमूमन मुश्किल माना जाता है। इसके अलावा तृतीय भाषा संस्कृत और उर्दू में भी विद्यार्थियों ने कमाल दिखाते हुए 100 में से 100 अंक तक प्राप्त किए। वहीं अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में शत-प्रतिशत अंक हासिल किए।

न्यूज ब्रीफ

मुख्यमंत्री को 'पर्सन ऑफ द ईयर' अवार्ड की ट्रॉफी भेंट

जयपुर। राजस्थान को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पायोनियर स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मिली 'पर्सन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड की ट्रॉफी प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अखिल अरोरा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजे को भेंट की। इस अवसर पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी मौजूद थे। राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करने और सेवाओं डिजिटलीकरण की दिशा में किये गए प्रयासों के लिए पहली बार किसी मुख्यमंत्री को यह सम्मान दिया गया। राजे की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित बी डब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड डिजिटल इंडिया समिट के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त किया था।

सरस मिल्क पाउडर भी एक किलो की पैकिंग में

जयपुर। सरस डेयरी ने दूध उपभोक्ताओं और व्यापारियों को एक बडी राहत दी है। डेयरी ने अब दूध, छाछ के बाद उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के लिए एक किलो की पैकिंग में स्किम्ड मिल्क पाउडर लॉन्च किया है। पाउडर की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। डेयरी ने दावा किया है कि इस एक पैकेट से 10 किलो दूध बनाया जा सकता है। पाउडर शहर के सरस बूथ, पार्लर और डेयरी में बने रिटेल काउंटर पर उपलब्ध होगा। पाउडर की लॉन्चिंग सोमवार को डेयरी एवं सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, चेयरमैन ओमप्रकाश पूनिया, और आरसीडीएफ एमडी जाकिर हुसैन ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किलक ने कहा कि दूध के व्यवसाय से किसानों की आय में दोगुना इजाफा हो सकता है।

सायबर क्राइम के 200 केसों की जांच को टीम

जयपुर | सायबर अपराधियों को पकड़ने के लिए जयपुर कमिश्नरेट के अफसरों ने प्राइवेट एक्सपर्ट और पुलिस अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई है। इसकी मॉनिटरिंग जयपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच के अधिकारी करेंगे। टीम को 56 पुलिस थानों में दर्ज सायबर अपराध से जुड़े 200 से ज्यादा मुकदमों की जांच करके आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। फर्जी फेसबुक आईडी, ई-मेल हैक, मोबाइल हैक करने करीब 25 प्रकरण और ठगी से संबंधित 175 मुकदमे शामिल हैं।

एसएमएस में भर्ती मरीज के परिजनों से दुकान से वाल्व मंगवाने के मामले में जांच के निर्देश

जयपुर। एसएमएस हॉस्पिटल के कार्डियोथोरेसिक विभाग में वाल्व उपलब्ध होने के बावजूद मरीज से निजी दुकान से वाल्व मंगवाने के मामले में दैनिक भास्कर में सोमवार को खुलासा होने के बाद चिकित्सा मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा भास्कर में प्रकाशित जेके लोन अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप और बच्चे की मौत व उदयपुर में सड़क पर ही महिला के प्रसव होने व समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने के मामले में भी मंत्री कालीचरण सराफ ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। मंत्री ने कहा है कि तीनों ही मामले गंभीर हैं। इनकी जांच करवाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट दी जाए।

वकीलों का बहिष्कार 22वें दिन भी जारी

जोधपुर। उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की मांग के विरोध में सोमवार को बाइसवें दिन भी जोधपुर के वकीलों की हड़ताल जारी रही। बड़ी संख्या में वकील अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और विरोध जताया। वकीलों ने हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। धरनास्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई।

5 विभागों में अब पंचायती राज संस्थाओं के जरिए होंगे तबादले

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने जारी किया आदेश

जयपुर। कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, प्रारंभिक शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कर्मचारियों का तबादला पंचायतीराज संस्थाओं के जरिए किया जाएगा। पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने का हवाला देकर राज्य सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यसचिव डीबी गुप्ता की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। पैतृक विभागों की ओर से किए जाने वाले तबादले अब निरस्त माने जाएंगे। मुख्यसचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर तबादले के अधिकार पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति में निहित होंगे। जिला परिषद क्षेत्र के भीतर तबादले के अधिकार जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति में निहित होंगे। अंतरजिला तबादला के अधिकार राज्य सरकार के पैतृक विभाग में निहित होंगे। शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से अहस्तांतरित संस्था से हस्तांतरित संस्था में स्थानांतरण के अधिकार पैतृक विभाग में रहेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र और हस्तांतरित संस्थाओं से अहस्तांतरित संस्थाओं में स्थानांतरण के आदेश पंचायती राज विभाग की सहमति के बाद पैतृक विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे।

पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मियों की हड़ताल खत्म

जयपुर। पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की हड़ताल सोमवार को खत्म हो गई। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने हमारी पांच मांगे मान ली हैं इसलिए हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया है। शर्मा ने बताया कि एलडीसी 2013 में सरकार ने पदोन्नति न देने की शर्त रखी थी, इस शर्त को हटाने पर सहमति बन गई है। इन कर्मचारियों को पदोन्नति के 5-5 अवसर दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मियों को भी अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा सहायक प्रशासनिक अधिकारी गजटेज अफसर बराबर माने जाएंगे। इसके अलावा अंतर जिला तबादले और राजस्व विभाग की तर्ज पर मंत्रालियक कर्मचारी बीडीओ तक प्रमोट हों इसके लिए कोटा रखने पर भी सहमति बनी है।

पेयजल संकट पर नीति आयोग उपाध्यक्ष ने सीएम से की चर्चा

जयपुर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। बैठक में आयोग के अधिकारियों के साथ राजस्थान में पेयजल की उपलब्धता और अकाल की स्थिति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। डॉ. कुमार ने केन्द्र की ओर से यथासंभव सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से कोपेनहेगन कन्सेन्सस के अध्यक्ष डॉ. लोम्बॉर्ग, उपाध्यक्ष रोनाल्ड, वरिष्ठ सलाहकार डॉ. मनोरमा बख्शी तथा टाटा ट्रस्ट की पॉलिसी हैड पूजा पार्वती ने भी मुलाकात की। इस दल ने राजस्थान सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं तथा नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में आ गया है। इस दौरान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता तथा आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लेक्चरर भर्ती-2015 के इंटरव्यू में करें शामिल

जयपुर। हाईकोर्ट ने कॉलेज लेक्चरर भर्ती-2015 के मामले में प्रार्थी को इंटरव्यू में शामिल करने का निर्देश देते हुए आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश वीके व्यास ने यह अंतरिम निर्देश सोमवार को राकेश बोकन की याचिका पर दिया। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया आरपीएससी ने 12 जनवरी 2015 को लेक्चरर भर्ती विज्ञापन जारी किया था। एक सितंबर 2016 को आरपीएससी ने संशोधित विज्ञापन जारी किया। याचिका में कहा कि प्रार्थी को इंटरव्यू में यह कहते हुए शामिल नहीं किया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने के समय न्यूनतम आयु 21 साल पूरी नहीं की थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि आरपीएससी के संशोधित विज्ञापन जारी करने के दौरान प्रार्थी न्यूनतम आयु सीमा पूरी कर चुका था।

राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा

चांदराना. राजेश पायलट की 18वीं पुण्यतिथि सोमवार को भंडाना स्थित स्मारक पर मनाई गई। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सभा में कांग्रेस नेताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

एक अप्रैल को 50% पद रिक्त होने पर ही प्रमोशन में मिलेगी एक साल अनुभव की छूट

जयपुर | समय से पहले प्रमोशन लेने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सरकार ने झटका दिया है। किसी भी विभाग में अब एक अप्रैल को 50 फीसदी पद रिक्त होने पर ही प्रमोशन में एक साल अनुभव की छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद 50 फीसदी सीटें खाली होने पर अनुभव में एक साल छूट देकर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से ताजा सकुर्लर निकाला गया है, जिससे कर्मचारी या अधिकारी दोहरा लाभ न लेने पाए। कार्मिक विभाग के पास अनुभव में एक साल छूट देने के लिए पूरे साल प्रस्ताव आ रहे थे। कई बार साल में दो-दो बार प्रमोशन के लिए डीपीसी करानी पड़ रही थी। केवल प्रमोशन का लाभ लेने के लिए जो सीटे मई, जून या सितंबर में खाली होनी होती थी, उस सीट को खाली मानकर प्रमोशन करा लिया जाता था। इससे राज्य सरकार को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था। इसको देखते हुए कार्मिक विभाग की ओर से नया गाइड लाइन तैयार किया गया है, जिसके तहत 31 मार्च को 50 फीसदी सीटें खाली होने की स्थिति में ही किसी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी को एक अप्रैल से मानकर अनुभव में एक साल की छूट देते हुए प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। ऐसा न होने पर समय से ही प्रमोशन के लिए डीपीसी कराई जाएगी। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। सीएम से मंजूरी के बाद सोमवार को कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। किसी विभाग में कर्मचारियों या अधिकारियों को एक साल पहले प्रमोशन चाहिए तो उसे कार्मिक विभाग में किस फारमेट में सूचनाएं भेजवानी है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने नया फारमेट भी जारी किया है, जिससे प्रस्ताव का परीक्षण करने में आसानी हो सके।

पुलिस ने कांग्रेस विधायक का समन तामील कराने भेजा, विधानसभा सचिवालय बोला-हमारा काम नहीं

नाराज विधानसभा सचिवालय ने गृह विभाग को भेजी शिकायत

मनोज शर्मा | जयपुर

राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के खिलाफ दर्ज आपराधिक एक मामले में समन तामील कराने विधानसभा सचिवालय को भेज दिया। इससे विधानसभा सचिवालय एवं पुलिस बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। नाराज विधानसभा ने गृह विभाग को शिकायत दर्ज करवाई है। संसदीय कार्य विभाग के विभिन्न पत्रों का हवाला देते हुए सरकार को लिखा है कि समन-वारंट तामील करवाने का जिम्मा विधानसभा के कार्य के दायरे में नहीं आता है। कार्यवाहक सचिव दिनेश कुमार जैन के अनुसार दो सप्ताह पहले ही इस बारे में गृह विभाग को हमने जानकारी भेज दी है । उन्हें याद दिलाया कि 2014 में सर्कुलर निकाला हुआ है। इसके बावजूद राज्य सरकार के विभाग बार-बार गल्तियां कर रहे हैं।

मामला, कांग्रेस विधायक एवं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना से जुड़ा है। चांदना के खिलाफ छह मामलों में अनुसंधान सीआईडी-सीबी में विचाराधीन है। इनमें दो मामले अशोक नगर, दो प्रकरण ज्योति नगर, एक-एक मामला उदयमंदिर एवं करौली में दर्ज है, जिनमें हत्या के प्रदेश, रास्ता रोकने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगी हुई है। मामले में अनुसंधान कर रही सीआईडी सीबी ने चांदना को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। लेकिन, वह पुलिस तामील नहीं करवा पा रही थी। इसलिए, पिछले दिनों अनुसंधान अधिकारी ने समन विधानसभा सचिवालय को भेज दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि बार-बार समन भेजने के बावजूद विधायक का कोई जवाब नहीं आया है।

चिंता : विधायक एवं सांसदों के खिलाफ दो दर्जन मामले

उधर, कार्यवाहक सचिव की ओर से एसीएस गृह को लिखी गई चिट्ठी पर मंथन चल रहा है। ताकि, कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। क्योंकि, विधायक एवं सांसदों के खिलाफ दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज है और इनमें कहीं कोई अन्य शिकायत नहीं आ जाए। गृह विभाग इसको लेकर कोई परिपत्र भी जारी कर सकता है।

गृह विभाग को पुलिस की शिकायत

कार्यवाहक सचिव दिनेश कुमार जैन ने कहा है संसदीय कार्य विभाग के आदेशानुसार समन-वारंट तामील करवाना विधानसभा सचिवालय का काम नहीं है। संसदीय कार्य विभाग के समय-समय पर जारी आदेश का हवाला देते हुए हमने गृह विभाग को यही लिखा है कि यह हमारा काम नहीं है। करीब दो सप्ताह पहले ही हमने सरकार को इसकी शिकायत कर दी है।

रिटायर्ड आरएएस के खिलाफ 24 साल पुरानी चार्जशीट रद्द

जयपुर | हाईकोर्ट ने 21 साल से लंबित मामले में रिटायर आरएएस अफसर के खिलाफ 29 जुलाई 1994 की चार्जशीट, 27 मार्च 1996 की जांच रिपोर्ट व 14 मार्च 1997 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने प्रार्थी को सेवा परिलाभ तीन महीने में देने को कहा। अदालत ने कहा प्रार्थी को दंडित कार्रवाई के तौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी मनमाना व गैर कानूनी है। अदालत ने यह आदेश सीएल वर्मा की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया प्रार्थी 1976 में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुआ और बाद में तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होते हुए 31 अक्टूबर 1991 को आरएएस सेवा कैडर में पदोन्नत हुआ।

पास होने की गारन्टी* अन्यथा शिक्षण शुल्क वापस
CBSE & RBSE
फेल विद्यार्थी साल बचाये
10वीं व 12वीं फेल 3 विषयों
की परीक्षा सितं.-अक्टू. 2018 में देकर साल बचायें
10वीं /12वीं फेल विद्यार्थी जो कि 2 विषय में उत्तीर्ण है इस योजना के माध्यम से केवल 3 विषयों की परीक्षा सितम्बर-अक्टूबर 2018 में देकर 10वीं /12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं।
10वीं व 11वीं एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करें
8वीं/ 9वीं फेल सीधे 10 वीं में प्रवेश लें
8वीं/9वीं या 10वीं फेल हों, किन्तु 1 जुलाई को 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, सीधे 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं तथा मार्च-अप्रैल 2019 में परीक्षा दे सकते हैं।
11वीं फेल सीधे 12वीं में प्रवेश लें
10वी पास या 11वीं फेल हों, जो 1 जुलाई को 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों सीधे 12वीं कक्षा में प्रवेश लेकर मार्च-अप्रैल 2019 में परीक्षा दे सकते हैं।
प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी
दसवीं
बारहवीं

पंजीयन विषय	कक्षा 10वीं	कक्षा 12वीं(कला)	कक्षा 12वीं(वाणिज्य)	कक्षा 12वीं(विज्ञान)
3 विषय	4700	4850	5050	5100
5 विषय	5180	5330	5530	5580

SC, ST, BPL, OBC अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को शिक्षण शुल्क में नियमानुसार छूट दी जाएगी
अन्तिम तिथि: 18.06.2018, विलम्ब शुल्क सहित 22.06.2018 एवं असाधारण विलम्ब 25.06.2018
हॉस्टल सुविधा बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष में फेल विद्यार्थी इसी वर्ष बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करें। माध्यम हिन्दी एवं अंग्रेजी
रविवार अवकाश आवेदन-पत्र कार्यालय समय (प्रातः 10 से 1 बजे तक) में 600/- देकर प्राप्त कर सकते हैं।
नोट- फोन पर विस्तृत एवं सम्पूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है। अतः विद्यार्थी विस्तृत एवं सम्पूर्ण जानकारी हेतु अभिभावकों के साथ प्रमाण-पत्रों सहित व्यक्तिगत सम्पर्क करें।
20 वर्षों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शक
PRERNA COLLEGE AJMER
प्रेरणा कॉलेज
91/10, सावित्री कॉलेज के सामने, सिविल लाईन्स, अजमेर- 305001
9079317875, 9079329654, 9079309716
फोन लाइनें प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ही खुली रहेंगी।